एमएसएमई से रोजगार देने में प्रदेश का पांचवां स्थान

निजी क्षेत्र में 11 लाख रोजगार का दावा ओडीओपी बनी गेमचेंजर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : दुनिया के साथ देश पर आए कोरोना संकट ने राज्यों के रोजगार प्रबंधन, वित्तीय क्षमताओं और नीतिगत सूझबूझ को भी परखा है। लॉकडाउन होने पर जब लाखों गरीब-मजदूर रोजगार से खाली हाथ हुए तो हर राज्य ने अपने प्रयास किए। उन प्रयासों के परिणाम के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रैंकिंग जारी की है, उसमें उत्तर प्रदेश ने टॉप-5 में जगह पाई है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के जरिये रोजगार देने में प्रदेश पांचवें स्थान पर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में एमएसएमई से रोजगार देने के मामले में प्रदेशवार सूची जारी की है। इसमें सर्वाधिक रोजगार देते हुए महाराष्ट्र पहले, तमिलनाडु दूसरे, गुजरात तीसरे, मध्यप्रदेश चौथे और उत्तर प्रदेश पांचवें स्थान पर है। यूपी ने राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों को रोजगार देने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। सरकारी प्रवक्ता का कहना है कि कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में दूसरे राज्यों से करीब चालीस लाख मजदूर यहां आए। उन सभी की स्किल मैपिंग कराते हुए सरकार ने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कुल 11 लाख श्रमिकों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करावा। प्रदेश में लगभग 90 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं। अपर मुख्य सचिव एमएसएमई डॉ.नवनीत सहगल का कहना है कि सरकार की इस उपलब्धि में सबसे बड़ी भूमिका एक जिला एक उत्पाद योजना ने निभाई है। छोटे-छोटे जिले भी रोजगार के केंद्र बने।

डिफेंस कॉरिडोर में निवेश को दो और अनुबंध

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : जेएनवी एरिका प्राइवेट लिमिटेड ने अलीगढ़ और लखनऊ में 75 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए दो अनुबंध उप्र औद्योगिक एवसंप्रेसवे विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के साथ किए हैं। यूपीडा मुख्यालय में मंगलवार को जेएनवी एरिका प्रा. लि. के साथ यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने दो अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। एक अनुबंध में कंपनी ने डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में दस एकड़ जमीन पर 50 करोड़ रुपये के निवेश का करार किया है।

अलीगढ़ नोड में पांच एकड़ जमीन पर 25 करोड़ रुपये के निवेश का दूसरा अनुबंध है। यूपीडा सीईओ ने कंपनी को आश्वासन दिया कि जल्द ही जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। जेएनवी एरिका के प्रतिनिधि विजय सुजान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उप्र का माहौल बदल गया है। अवस्थी ने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर के लिए चयनित सभी छह नोड में से अलीगढ़, कानपुर, झांसी और चित्रकूट में 1465 हेक्टेयर भूमि को चिह्नित किया गया है। अलीगढ़ में अधिग्रहित पूरी जमीन का आवंटन यूपीडा द्वारा निवेशकों को किया जा चुका है। वहां निवेश करने के लिए 20 कंपनियों के साथ यूपीडा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत कुल 1021 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इन 20 में से 12 कंपनियों को जमीन दे दी गई है।

75 करोड़ रुपये निवेश करेगी जेएनवी एरिका लखनऊ और अलीगढ़ में

इनको मिली अलीगढ़ में जमीन

- एकर रिसर्च लैब्स- दस हेक्टेयर
- एलन एंड एलकन प्रा.लि.- आठ हेक्टे.
- पीबीएम ह्यूलेशंस- 0.40 हेक्टेयर
- नित्या क्रिएशंस इंडिया- 1.50 हेक्ट.
- दीप एक्सप्लो इक्विपमेंट इंडिया- एक हेक्टेयर
- श्रीदा उद्योग- एक हेक्टेयर
- प्रिसीजन प्रोडक्ट्स- एक हेक्टेयर
- पी-2 लॉजिटेक- दो हेक्टेयर
- जय साई अनु ओवरसीज- 4.5 हेक्टे.
- कोबरा इंडस्ट्रीज- 0.25 हेक्टेयर
- न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी- 3.5 हेक्टेयर
- वैरिविन डिफेंस प्रा.लि.- 0.50 हेक्टे.